हिन्दी साप्ताहिक

RNI. No. MPHIN /2021/85636

भुआणा की माटी

संपादकः- लोमेश कुमार गौर

साप्ताहिक
भुआणा की माटी
में रचनायें लेख
कवितायें एवं
विज्ञापन
प्रकाशनार्थ
आमंत्रित है।

वर्ष-05 अंक-48 | हरदा, बुधवार 25 फरवरी से 03 मार्च -2026 | पृष्ठ-08 मूल्य 05 रूपये

सार समचार

आज हरदा प्रवास पर आएंगे सैनिक कल्याण संचालक

हरदा। संचालक सैनिक कल्याण मप्र भोपाल ब्रिगेडियर अरुण नायर, सेना मेडल (से.नि.) 25 फरवरी को हरदा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से सीधा संवाद करेंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 फरवरी को वे हरदा जिले के पूर्व सैनिकों, शहीदों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याएं सुनेंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर अनुराग सक्सेना (से.नि.) ने अनुरोध किया है कि जिले के सभी पूर्व सैनिक एवं वीरनारियां निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें। कार्यक्रम संबंधी अधिक जानकारी के लिये कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07574-254465 एवं कल्याण संयोजक के मोबाइल नम्बर 9454504891 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम 27 फरवरी को

हरदा। भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर के द्वारा जिला प्रशासन हरदा के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सुमेघा सुमन ने बताया कि यह जागरूकता कार्यक्रम 27 फरवरी को होटल रुद्राक्ष पैलेस हरदा में सुबह 10.30 बजे से किया जाएगा। उन्होने बताया कि कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्टर्ड लाभार्थी सीधे उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। इसके लिए पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को उद्यमिता, वित्तीय सहायता, ईकॉमर्स, केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं, ट्रेनिंग एवं टूल किट आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, हथकरघा विभाग, शासकीय आईटीआई विभागों के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जाएगी।

भारतीय किसान संघ 27 फरवरी को हरदा में करेगा आंदोलन

गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीदने की मांग, राजस्थान सरकार का उदाहरण दिया

हरदा। भारतीय किसान संघ ने गेहूं के लिए 2700 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है। इस मांग को लेकर संघ 27 फरवरी को हरदा जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेगा। संघ के जिला प्रवक्ता राजनारायण गौर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वर्तमान समर्थन मूल्य किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने राजस्थान सरकार का उदाहरण दिया, जहां किसानों से गेहूं 2735 प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है। गौर ने कहा कि अन्य वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे खेती घाटे का सौदा बन गई है। उन्होंने मक्का का उदाहरण देते हुए बताया कि इसका समर्थन मूल्य 2400 निर्धारित है, लेकिन मंडियों में यह 1200 से 1300 प्रति क्विंटल बिक रहा है। इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 और उस पर 15 बोनस देने की घोषणा की है, जिससे कुल मूल्य 2600 प्रति क्विंटल होता है। भारतीय किसान संघ इस मूल्य को कम मानते हुए जिले की सभी इकाइयों से जुड़े किसानों के साथ कृषि उपज मंडी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। संघ ने अन्य मांगों में खरीफ 2025 की बीमा राशि सभी किसानों को शीघ्र दिलाना, किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराना और ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए जिले की सभी नहरों में पर्याप्त पानी देना शामिल है। गंजाल मोरण्ड सिंचाई परियोजना का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, ई-टोकन द्वारा खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने और जिले में किसानों के खेतों तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कर ग्रेवल मार्ग बनाने की भी मांग की गई है। बैठक में जिला सदस्य विनय पटेल, जिला युवा वाहिनी संयोजक रामकृष्ण कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष विजेश मुकाती, उपाध्यक्ष सुरेश जोशी, तहसील मंत्री जितेंद्र शर्मा, तहसील सदस्य नीरज कुशवाहा, राजकुमार बोरदे, दिनेश राजपूत, जितेंद्र राजपूत और हरिओम गौर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

एसी का तापमान 26 डिग्री सेट करने पर बिजली बिल में 30 फीसदी तक की कमी

हरदा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपना कर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। शोध के अनुसार, प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्प्लिट एसी की ऊर्जा खपत में 6 प्रतिशत की कमी आती है। मध्य क्षेत्र विद्युत विरण कंपनी के अनुसार गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर के लगातार चलने के कारण बिजली का बिल चिंता का एक बड़ा कारण है। लेकिन एयर कंडीशनर का समझदारी से उपयोग करके आप इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जारी सुझावों में सबसे महत्वपूर्ण है कि एसी को ऊंचे लेकिन आरामदायक तापमान पर चलाना चाहिए। विभिन्न एजेंसियों के शोधों से साबित हुआ है कि एसी के तापमान को 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से बिजली के बिल को 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। दरसअल कमरे को तुरंत ठंडा करने के लिए तापमान को 18 डिग्री तक कम करना एक आम गलतफहमी है। जबकि 26 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में लगने वाला समय वही रहता है। चाहे आप एसी का तापमान 18 या 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें। लेकिन जब आप कम तापमान सेट करते हैं, तो कमरे के तापमान को कम करने के लिए कंप्रेसर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप अधिक बिल आता है। यहां तक कि अगर आप थर्मोस्टेट को 18 डिग्री पर सेट करने के बाद कुछ मिनटों के भीतर एसी बंद कर देते हैं, तो विभिन्न लीक के माध्यम से ठंडी हवा के फैलने से तापमान तेजी से बढ़ जाएगा।

कचरे का बोझ

सुप्रीम कोर्ट की इस गंभीर चिंता से सहमत हुआ जा सकता है कि ठोस कचरे का निस्तारण एक पर्यावरणीय मुद्दा मात्र नहीं है बल्कि यह जन-स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिये भी गंभीर चुनौती है। निःसंदेह, जब हम विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य हासिल करने की बात करते हैं तो नागरिक जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन भी एक अनिवार्य शर्त है। निःसंदेह, देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी नागरिक चुनौती बनी हुई है। देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र, कचरे के पहाड़ों से दबे लैंडफिल, अनुचित अपशिष्ट के अलग-अलग न होने तथा कचरे के प्रभावी निपटान की चुनौती से जूझ रहे हैं। ठोस कचरा निस्तारण से जुड़े नये नियम लागू होने से कुछ सप्ताह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने देश में दशकों पुराने ठोस अपशिष्ट उपचार नियमों के अनुपालन में कोताही को लेकर चिंता व्यक्त की है। अदालत का मानना है कि बढ़ते कचरे का बोझ नागरिक जीवन की सुगमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा स्मार्ट सिटीज जैसी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों को उजागर किया है। यही वजह है कि न्यायालय ने समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए नियमों को सख्ती से लागू करने तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है। सही मायनों में यह समय की भी जरूरत है। दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने स्थानीय निकायों और निर्वाचित प्रतिनिधियों मसलन पार्षदों व कॉर्पोरेटरों को दायित्व दिया है कि वे क्षेत्र के नागरिकों में स्वच्छता व ठोस कचरे के निस्तारण हेतु जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की पहल करें। जनजागरण से ही विकट होती समस्या के निस्तारण में मदद मिल सकती है। इस दिशा में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक चरण में दायित्व निर्वहन में विफल रहने पर जुर्माना विकल्प हो सकता है। वहीं बार-बार नियमों का उल्लंघन करने कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य है। निःसंदेह, ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता स्वच्छता और ठोस कचरे के निस्तारण में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करना कर्तव्य की अनदेखी करने पर कड़ा संदेश दे सकती है।

ट्रेड यूनियन आंदोलन का बदलता स्वरूप

विभूति गौर

12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देशव्यापी बंद के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य संगठित श्रमिक शक्ति का प्रदर्शन करना था। हालांकि, वास्तविकता में कई राज्यों से आई रिपोटों में अधिकांश शहरों में सामान्य व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहने, सार्वजनिक परिवहन के संचालन और केवल कुछ स्थानों पर आंशिक औद्योगिक व्यवधान की स्थिति सामने आई। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई इकाइयों में आंशिक उपस्थिति दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यापक स्तर पर इस बंद का प्रभाव सीमित रहा। यह स्थिति भारत के श्रम बाजार की गहरी संरचनात्मक वास्तविकताओं को दर्शाती है। आज भी लगभग 85-90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां न तो स्थायी रोजगार सुरक्षा है और न ही औपचारिक श्रम अधिकारों का लाभ। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग स्व-रोजगार, ठेका श्रम, छोटे व्यापार या प्लेटफॉर्म आधारित गिग इकोनॉमी में कार्य कर रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में पारंपरिक ट्रेड यूनियन मॉडल-जो बड़े कारखानों और दीर्घकालिक सामूहिक सौदेबाजी पर आधारित था-अब सीमित वर्ग तक ही प्रभावी रह गया है। 12 फरवरी के बंद ने यह भी दिखाया कि कई क्षेत्रों में बंद का प्रभाव स्वैच्छिक भागीदारी से अधिक अवरोधों, प्रतीकात्मक प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्यवाही तक सीमित रहा। आम नागरिकों के लिए ऐसे बंद अक्सर एकजुटता के बजाय असुविधा और आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। यात्रियों को परेशानी, छोटे व्यापारियों को नुकसान, आवश्यक सेवाओं में बाधा और दैनिक मजदूरी पर निर्भर लोगों की आय में कटौती जैसी समस्याएं सामने आती हैं। परिणामस्वरूप, बंद को अब लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रभावी साधन की बजाय रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा के रूप में देखा जाने लगा है। इस दूरी के पीछे कई कारण हैं। रोजगार के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है, जबकि यूनियनों की रणनीतियां अपेक्षाकृत पारंपरिक ढांचे तक सीमित बनी हुई हैं। यूनियन नेतृत्व मुख्यत: सार्वजनिक उपक्रमों और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां संस्थागत पकड़ तो मजबूत है लेकिन व्यापक प्रतिनिधित्व कमजोर है। साथ ही, यूनियनों के बीच विभाजन भी संदेश और प्रभाव दोनों को कमजोर करता है। आधुनिक रोजगार की अनिश्चितता भी श्रमिकों को लंबे आंदोलन से दूर रखती है। लेख का निष्कर्ष यह है कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में बदलाव के इस दौर में भारत के पास विकास का बड़ा अवसर है। ऐसे समय में ट्रेड यूनियनों के लिए यह आवश्यक है कि वे केवल बंद और विरोध तक सीमित न रहकर कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, लाभों की पोर्टेबिलिटी, कार्यस्थल सुरक्षा और विवाद समाधान जैसे विषयों पर ठोस एवं व्यावहारिक प्रस्ताव रखें। तभी वे श्रमिक हितों के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के साझेदार बनकर अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव को बनाए रख सकेंगे।

(लेखक के स्वयं के विचार है)

जाति संघर्ष का सर्वसमावेशी समाधान वक्त की जरूरत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा-निर्देशों से ना सिर्फ जाति विमर्श केंद्र में आ गया है, बल्कि हिंदू समाज जातीय खांचे में बंटता नजर आ रहा है। आर्थिक और शैक्षिक विकास की वजह से जाति विभाजन की जो रेखाएं मध्यम पड़ने लगी थीं, वे एक बार फिर गहरी होती नजर आ रही है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जैसा स्पष्ट विभाजन हिंदू समाज में दिख रहा था, कुछ उसी राह पर एक बार फिर समाज बढ़ता दिख रहा है। जाति के तवे पर राजनीतिक रोटी सेंकने वाले कुछ दल यूजीसी की गाइडलाइन को लागू करने के लिए छात्रों के बीच जाति विमर्श की आंच को हवा दे रहे हैं तो इस गाइडलाइन के विरोध में खड़े सवर्ण समाज के लोग भी अपने समाज के छात्रों को लामबंद करने में प्राणपण से जुटे हुए हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह नया राजनीतिक विमर्श खड़ा हुआ, जिससे कुछ राजनीतिक दलों और शख्सियतों को उभरने का मौका मिला, कुछ वैसे ही हालात एक बार फिर बनते दिख रहे हैं। अगर यूजीसी गाइडलाइन का सर्वसमावेशी हल नहीं खोजा गया तो हिंदुत्व की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। हिंदू एकता का सपना भी खतरे में पड़ सकता है। राजनीति के बारे में एक धारणा है। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास ने जाति विभाजन को जहां कमजोर किया, वहीं राजनीति इसे जिंदा करने में सफल हुई है। सामाजिक यात्रा में पिछड़ी रह गई जातियों के उत्थान के नाम पर राजनीति ने जाति विमर्श को केंद्र में लाने का सबसे बड़ा योगदान विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है, जिन्होंने देवीलाल के राजनीतिक रसूख को काबू में करने के लिए 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर पड़ी धूल को झाड़ा और उसे लागू कर दिया। पैंतीस साल पहले के उस फैसले ने समाज को बुरी तरह विभाजित कर दिया। मंडल आयोग के खिलाफ तकरीबन समूचा उत्तर भारत धधक उठा था। सवर्ण समुदाय के छात्रों और नौजवानों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था। उन्होंने खुद को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह कविता भी करते थे। कवि को लेकर धारणा है है कि वह कोमल हृदय का स्वामी होता है। लेकिन आग की लपटों के बीच धू-धूकर जवानी को जलती देखकर भी कवि हृदय प्रधान मंत्री नहीं पसीजे थे। उस दौर के शरद यादव सवर्ण समाज के कटु आलोचक और पिछड़ावादी राजनीति के प्रबल पैरोकार के रूप में उभरे। मंडल आयोग की रिपोर्ट से समाज के बीच जो खाई पैदा हुई, बाद की राजनीति ने उसे और ज्यादा चौड़ा और गहरा ही किया है। पिछड़ों को आरक्षण को समाज ने स्वीकार कर लिया था, तभी दूसरे सवर्ण और मनमोहन सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने साल 2006 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की शुरूआत कर दी। इसके विरोध में एक बार फिर युवा राजनीति उभरी। यूथ फॉर इक्वलिटी के बैनर तले दिल्ली में इस फैसले के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर पड़े। इस आंदोलन के चलते भी सामाजिक विभाजन बढ़ा। शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण के विरोधी समुदायों और इसके समर्थक समुदायों के बीच एक बार फिर विभाजक रेखा गहरी हुई। इससे भी देश उबर रहा था कि यूजीसी की गाइडलाइन आ गई और फिर से एक बार भारतीय समाज गहरे अंतरद्वंद्व और सामाजिक संघर्ष से जूझने लगा। यह संघर्ष अभी समाज में सीधे तो नहीं दिख रहा, लेकिन विश्वविद्यालयों के परिसर इसके चलते उबल रहे हैं। एक तरफ इस गाइडलाइन के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ उसके विरोधी। आज पिछड़ावाद, दलितवाद, अल्पसंख्यकवाद और महिलावाद का जोर है। इन तबकों के उभार के विचार को सामाजिक न्याय करीब साढ़े तीन दशकों से स्वीकार किया जा रहा है। इन वादों को सामाजिक लोकवृत्त यानी पब्लिक स्फीयर के केंद्र में लाने का विचार समाजवादी राजनीतिक दलों का रहा है, लेकिन इसे मूर्त रूप में लाने वाले कांग्रेसी मूल के राजनेता ही रहे हैं। समाजवादी दलों के ही परोक्ष समर्थन से पहली बार तीस मई 1933 को बिहार के मौजूदा रोहतास जिले के करगहर में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी।

खिरकिया में युवा से मारपीट, जान से मारने की धमकी

सर्व ब्राह्मण समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग

खिरकिया। खिरकिया में सर्व ब्राह्मण समाज ने मंगलवार को एसडीएम के नाम का आवेदन एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार प्रिंसी जैन को एक ज्ञापन सौंपा। समाज ने अपने युवा सदस्य अनुरूप बायवर के साथ हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। समाज के अध्यक्ष पं. मनीष (मोनु) तिवारी (एडवोकेट) ने बताया कि यह घटना 23 फरवरी 2026 को रात करीब 9:30 बजे वंदना चौराहे पर हुई थी। आरोप है कि वार्ड नंबर 7, खिरकिया निवासी शेख इमरान (पिता शेख वहीद) ने अनुरूप बायवर को बुलाकर मारपीट की। ज्ञापन के अनुसार, शेख इमरान ने अनुरूप बायवर पर व्हाट्सएप ग्रुप पर बहस करने और पैसों की मांग का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस मारपीट में अनुरूप बायवर की बाईं आंख के नीचे और बाएं गाल पर चोटें आईं। इस संबंध में अनुरूप बायवर ने पुलिस थाना छीपाबड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। समाज ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि वर्तमान में रमजान का महीना चल रहा है और होली जैसा बड़ा हिंदू त्योहार भी आने वाला है। ऐसे समय में शेख इमरान द्वारा की गई यह घटना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है। समाज ने मांग की है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए, जो दो समुदायों के बीच बड़ी घटना या दुर्घटना करवा सकते हैं। समाज ने ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की है। ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शेख इमरान के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो समाज को आगे की कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपते समय समाज के कई सदस्य और अन्य लोग मौजूद थे।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनी नागरिकों की समस्याएं

हरदा। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित 'जनसुनवाई' कार्यक्रम में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवीण इवने, एसडीएम खिरकिया सुशिवांगी बघेल सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में हरदा निवासी श्रीमती सलोनी साहू ने कलेक्टर जैन को आवेदन देकर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की, जिस पर उन्होने मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा को आवेदिका की पात्रता अनुसार योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। ग्राम पिडगांव के किसानों ने आवेदन देकर खेत में जाने के रास्ते पर पुलिया बनवाने की मांग की, जिस पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को किसानों की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई में आउटसोर्स डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स ने तीन माह का लंबित वेतन तथा एरियर भुगतान कराने की मांग की, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदकों की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। हरदा निवासी आदित्य सिंह ने ग्राम गोंदागांव स्थित अपनी जमीन के सीमांकन की पुष्टी कराकर रिकार्ड दुरूस्त कराने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार टिमरनी को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई में हरदा निवासी उषा बाई ने आवेदन देकर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने तथा खाद्यान्न पर्ची दिलाने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा को पात्रता अनुसार आवेदिका की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये।

हरदा में मैकेनिक कटोरा लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा

हरदा। हरदा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक मैकेनिक अपनी मजदूरी का भुगतान न मिलने पर कटोरा लेकर पहुंचा। खिरकिया निवासी भोला सैनी ने बताया कि सिराली नगर परिषद ने चार महीने पहले उससे एक कचरा गाड़ी की मरम्मत करवाई थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सैनी के अनुसार, उसने कचरा वाहन की मरम्मत की थी और उसमें 8,000 रुपए का यूरिया क्वालिटी सेंसर भी लगाया था। मरम्मत और पुर्जे सहित कुल 12,500 रुपए का भुगतान उसे मिलना था। मैकेनिक ने आरोप लगाया कि भुगतान के लिए बार-बार अनुरोध करने और जिला कार्यालय में जनसुनवाई के साथ-साथ 181 पर शिकायत करने के बावजूद उसे पैसे नहीं मिले। उसकी शिकायतें बिना उसकी सहमति के निराकृत कर दी गईं। सैनी का दावा है कि नगर परिषद ने झूठी जानकारी दी कि उसने कोई वाहन ठीक नहीं किया या कोई पुर्जा नहीं लगाया, और उसे पैसे वसूलने का प्रयास करने वाला बताया। इस मामले पर कलेक्टर जैन ने कहा कि संबंधित व्यक्ति ने गाड़ी की मरम्मत का काम किया था और उसके भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, कलेक्टर ने यह भी बताया कि जब मैकेनिक को गाड़ी से निकाला गया पुराना सेंसर वापस करने को कहा गया, तो उसने किसी और गाड़ी का सेंसर दे दिया। कलेक्टर जैन ने आशंका जताई कि मैकेनिक ने वास्तविक सेंसर देने में धोखाधड़ी की है। उन्होंने नगर पालिका अधिकारियों को मैकेनिक का बनता भुगतान करने और यदि धोखाधड़ी हुई है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत किसानों को मिल रही सोलर पंप की सौगात

हरदा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पी.एम.कुसुम योजना का घटक-ब प्रदेश में ''प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना'' के नाम से संचालित है, जिसके अंतर्गत हरदा जिले के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा और भी आसान हो रही है। जिले में ऑफग्रिड सोलर पंपों की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी तथा खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रभारी जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के लिए अत्यंत सरल एवं लाभकारी वित्तीय ढांचा तय किया गया है। योजना के तहत किसान अंशदान केवल 10 प्रतिशत, केंद्र सरकार का अनुदान 30 प्रतिशत तथा बैंक ऋण शेष 60 प्रतिशत है। योजना के तहत ऋण की गारंटी मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जा रही है। ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया

योजना का लाभ प्राप्त करने एवं वेंडर द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए ऋण स्वीकृति अनिवार्य है। इसके लिए- कुसुम-बी राज्य पोर्टल से एआईएफ (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) में ऑनलाइन आवेदन नोडल बैंक में किसान का खाता एवं सीआईएफ की उपलब्धता, डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से बैंक द्वारा ऋण की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है।

जिले में अब तक की प्रगति

प्रभारी अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री जैन ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक हरदा जिले में 361 आवेदनों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से किसानों को दिन के समय निर्बाध सिंचाई, कम लागत में खेती तथा पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का लाभ मिल रहा है।

खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में अग्रणी स्थान

मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में शामिलः सीएम यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य खाद्यान्न, दलहन तथ तिलहन फसलों के उत्पादन में शीर्ष तीन राज्यों में शामिल रहा है। मध्यप्रदेश ने कुल खाद्यान्न उत्पादन में 46.63 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 13.04 प्रतिशत है। राज्य कुल दलहन फसल उत्पादन

में देश में प्रथम स्थान पर हैं। तिलहन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को बढ़ाने एवं उनके समग्र कल्याण के उद्देश्य से वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। गेहूं उत्पादन में राज्य ने 24.51 मिलियन टन उत्पादन किया और लगभग 20.78 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया। राज्य मक्का उत्पादन में भी अग्रणी रहा, 6.64 मिलियन टन उत्पादन के साथ मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय हिस्सेदारी में लगभग 15.30 प्रतिशत योगदान रहा, जिससे यह देश का प्रमुख उत्पादक राज्य बना। मोटे अनाज (न्यूट्री/कोर्स सीरियल्स) के उत्पादन में भी राज्य ने 7.78 मिलियन टन उत्पादन करते हुए लगभग 12.17 प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज की और देश में तृतीय स्थान हासिल किया।

आज होगा आजीविका विपणन क्षमतावर्धन कार्यशाला का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 फरवरी बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्व-सहायता समूहों की आजीविका मिशन क्षमतावर्धन कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के मार्केटिंग के तहत क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को उत्पाद विक्रय के लिये राष्ट्र स्तरीय वृहद बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं राज्यमंत्री मती राधा सिंह उपस्थित रहेंगी। आजीविका मिशन की सीईओ मती हर्षिका सिंह ने बताया है कि स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित-उत्पादों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिये ई-मार्केट पोर्टल एक उत्तम व्यवस्था है।

मध्यप्रदेश दलहन उत्पादन शीर्ष स्थान बरक़रार

दलहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल दलहन उत्पादन में 5.24 मिलियन टन उत्पादन किया और 20.40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। चना उत्पादन में राज्य 2.11 मिलियन टन उत्पादन और लगभग 19.01 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष तीन राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा।

तिलहन फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य

तिलहन क्षेत्र में भी राज्य की स्थिति मजबूत रही। कुल तिलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश ने 8.25 मिलियन टन उत्पादन करते हुए लगभग 19.19 प्रतिशत राष्ट्रीय हिस्सेदारी दर्ज की एवं देश से दूसरा स्थान हासिल किया। विशेष रूप से सोयाबीन उत्पादन में राज्य ने 5.38 मिलियन टन उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 35.27 प्रतिशत है और इसे देश के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में स्थापित करता है। राज्य में मूंगफली का उत्पादन 1.55 मिलियन टन रहा जो कि देश के कुल उत्पादन का 12.99 प्रतिशत रहा। मूंगफली उत्पादन में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश में केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि विकास योजनाओं रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण कार्यक्रम, मांग आधारित कृषि के लिए फसलों का विविधीकरण, रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।

बीएसएसएस एनएसएस सात दिवसीय शिविर हुआ संपन्न

भोपाल। भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित सात दिवसीय विशेष इकाई शिविर का समापन समारोह गरिमापूर्वक संपन्न हुआ। प्रातः प्रभात फेरी, पीटी एवं योग के साथ दिन का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात नाश्ते के उपरांत प्रातः 10:30 बजे बौद्धिक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉ. अशोक कुमार श्रोति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ एवं डॉ. राजकुमार वर्मा युवा अधिकारी, भारत सरकार उपस्थित रहे। दोनों वक्ताओं ने स्वयंसेवकों को सेवा, नेतृत्व एवं राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित किया। इसी अवसर पर माय भारत पोर्टल पर संचालित माय भारत बजट क्वेस्ट में भी स्वयंसेवकों की सहभागिता कराई गई। इसके पश्चात समापन समारोह की तैयारियाँ की गईं। प्रांगण की स्वच्छता कर सुंदर सजावट, चित्रांकन एवं पुष्प-सज्जा से परिसर को आकर्षक रूप प्रदान किया गया। रात्रि में आयोजित समापन समारोह में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ फादर जॉन पी. जे. की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथियों के रूप में डॉ. अनंत कुमार सक्सेना कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, राहुल सिंह परिहार ईटीआई प्रशिक्षक, कार्यक्रम अधिकारी मुक्त इकाई बीयू एवं अक्षय तिवारी प्राध्यापक कार्यक्रम अधिकारी, शासकीय महाविद्यालय कुरवाई, जिला विदिशा उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण से हुआ।

रास्ता भटकी बालिकाओं को परिजनों से मिलाया

भोपाल। डायल-112 केवल आपात स्थितियों में सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों, महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा में मानवीय संवेदनशीलता का भरोसेमंद सहारा है। इंदौर जिले में डायल-112 जवानों ने त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से रास्ता भटकी दो मासूम बालिकाओं को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाकर जन-सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। दिनांक 24 फरवरी को इंदौर के थाना एरोड्रम क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल वेयर हाउस के सामने दो बालिकाएँ मिलने की सूचना डायल-112 राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल को प्राप्त हुई। सूचना में बताया गया कि दोनों बालिकाएँ घर का रास्ता भटक गई हैं तथा पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही थाना एरोड्रम क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुँचकर डायल-112 स्टाफ सउनि श्री कैलाश मेडा, आरक्षक श्री पुष्पेंद्र शर्मा एवं पायलट श्री अजय प्रजापति ने दोनों बालिकाओं को अपने संरक्षण में लिया। बालिकाएँ स्कूल की यूनिफॉर्म में थीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे विद्यालय जाने की तैयारी में थीं। डायल-112 जवानों ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए संबंधित स्कूल से संपर्क किया, जहाँ से बालिकाओं के परिजनों की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही परिजन चौकी पहुँचे, जहाँ पहचान एवं सत्यापन उपरांत दोनों बालिकाओं को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

राज्यपाल पटेल द्वारा मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना की समीक्षा की

क्रियान्वयन में पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता जरूरीः राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना सबसे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का उपक्रम है। योजना की प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन में गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उनके हितों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। राज्यपाल पटेल मंगलवार को पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना के संबंध में लोकभवन में चर्चा कर रहे थे। बैठक का आयोजन जनजातीय प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था। इस अवसर पर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पशुपालन एवं डेयरी विकास लखन पटेल, जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर,

राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास उमाकांत उमराव, जनजातीय प्रकोष्ठ के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना अति पिछड़ी और गरीब पी.वी.टी.जी. जनजातियों बैगा, भारिया एवं सहरिया के कल्याण के लिए क्रियान्वित है। इस योजना की प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन में पारदर्शिता, तत्परता के साथ ही संवेदनशील मनोभाव का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के पी.वी.टी.जी. जनजातीय जनसंख्या वाले सभी जिलों को योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए। राज्यपाल को बताया गया कि योजना के तहत पशु वितरण कार्य की सामुदायिक निगरानी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सभी दुग्ध समितियों तथा संघों के द्वारा माह में 10-10 दिन के अंतराल पर तीन निश्चित तिथियों पर भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। दूध के मूल्य में भी 2 से साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि की गई है। योजना में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मिल्क रूट तथा परिवहन की सुगमता वाले ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर हितग्राहियों के चयन के साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य ग्रामों में भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

7 नाबालिगों को नशे का सेवन करते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार

अवैध हुक्का-तंबाकू बिक्री पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

विदिशा। सोमवार को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले डंडापुरा क्षेत्र में नाबालिग बच्चों द्वारा नशे का सेवन किया जा रहा था। इस मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और साथ नाबालिग बच्चों को मौके से थाने लेकर आए। यहां से उन्हें बाल न्यायालय में पेश किया गया और बाल सुधार गृह भेजा गया। वहीं पुलिस ने अवैध हुक्का-तंबाकू बिक्री पर सख्त कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।

नशे का कारोबार धीरे-धीरे बच्चों की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। नशे के कारोबारी छोटे-छोटे बच्चों को भी नशे की लत लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि कम उम्र के बच्चे भी अब नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले डंडापुरा क्षेत्र में सामने आया है। यहां सात नाबालिग बच्चों को नशे का सेवन करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया है।

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया कि पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश पर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर नाबालिग नशे का सेवन करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर धर पकड़ की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में डंडापुरा क्षेत्र में नाबालिग बच्चों द्वारा अवैध नशे का सेवन करने की शिकायत मिली थी। जिस पर मौके पर पुलिस को भेजकर जांच पड़ताल की गई तो पाया कि सात नाबालिग बच्चे अवैध नशे का सेवन कर रहे थे और पुलिस द्वारा उन्हें पकड़कर थाने लाया गया है और सभी को बाल न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से सुधार गृह में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों से नशे की लत छुड़ाने के लिए उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वह नशे की गिरफ्त से बाहर आ सकें। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध हुक्का-तंबाकू बिक्री पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

21 फरवरी को प्राप्त सूचना के आधार पर नीमताल चौराहा क्षेत्र में स्थित लूट ऑप्टिकल दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान दुकान संचालक रोहित राजपूत पिता सुरेश राजपूत द्वारा हुक्का एवं तंबाकू फ्लेवर के पैकेट अवैध रूप से विक्रय किए जाने की पुष्टि हुई। तलाशी के दौरान दुकान से शीशे एवं चीनी मिट्टी से बने कुल 10 हुक्के, हुक्का प्रयुक्त सिल्वर पन्नी का एक पैकेट, 01 नोजल पैकेट, 05 हुक्का पाइप, 70 हुक्का तंबाकू फ्लेवर पैकेट बरामद किए गए है। उक्त सामग्री के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/2026 धारा 6/24 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2023 तथा धारा 271 बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी आनंद राज, उप निरीक्षक रणवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक मुकेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक विजय गुप्ता, आरक्षक राघवेंद्र सिकरवार, आरक्षक शिशुपाल सिंह दांगी, आरक्षक विजय सावरकर एवं आरक्षक सुनील कुमार की सराहनीय भूमिका रही।

लेट्राइड का अवैध रूप से भंडारण और परिवहन का आरोप जिम्मेदार अधिकारियों से कार्यवाही की मांग

ब्योहारी। रेलवे स्टेशन ब्योहारी के पास निजी भूमि मे बिना किसी मंजूरी के भूरे रंग के मिट्टी का भंडारण किया जा रहा है। उक्त स्थान मे भंडारण किये जाने संबंधी किसी प्रकार का कोई सूचना बोर्ड नहीं लगा है। सूत्रों द्वारा उक्त मिट्टी को मालवाहक ट्रेन से रेनूकोट से आने और रेलवे स्टेशन मे खाली होने की बात बतायी जा रही है। उनका कहना है कि अल्ट्राटेक कम्पनी बघवार रेलवे की पैनाल्टी से बचने के लिये वहाँ से उसे उठावा कर बिना किसी मंजूरी के अवैधानिक रूप से लेट्राइड का भंडारण निजी भूमि पर करा कर परिवहन कराया जा रहा है। वंही खनिज विभाग उसे लेट्राइड की जगह कुछ और ही बता रही है जिसे खनिज विभाग से भंडारण एवं परिवहन मे छूट होने की बात कही

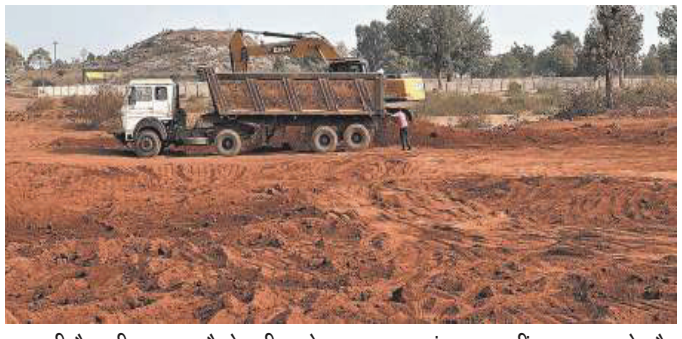

जा रही है हकीकत क्या है ये वही जाने किन्तु जानकारों द्वारा खनिज विभाग से मिली भगत कर बिना किसी मंजूरी के भंडारण करना और अवैध रूप से परिवहन किये जाने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि चाहे कोई भी मिट्टी हो यदि उसका ब्यवसायिक उपयोग हो रहा है तो उसके भंडारण के लिये खनिज विभाग से मंजूरी लेना अवश्यक है बिना किसी मंजूरी के उसका भंडारण नहीं कर सकते है हकीकत का खुलासा उच्चस्तरीय जांच से ही हो सकता है।

इनका कहना है-

मैं एक बार जा कर देखा हूँ। वह लेट्राइड नहीं है वह कुछ और ही मटेरियल है। वह खनिज में नहीं आता है।

राहुल साण्डिल्य
खनिज अधिकारी शहडोल

मेला से लापता 14 वर्षीय नाबालिग का अब तक सुराग नहीं

शहडोल। जनपद ब्योहारी क्षेत्र के गोदावल मेला से लापता हुई एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। बच्ची के गायब होने से परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार ग्राम छतैनी निवासी फरियादी रामजस बसोंर ने बताया कि उनके परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं। तीनों बड़े बच्चों की शादी हो चुकी है। सबसे छोटी बेटी कविता बसोंर (उम्र लगभग 14 वर्ष 8 माह) 20 जनवरी को अपने परिवार के साथ गोदावल मेला देखने गई थी। दोपहर लगभग 2 बजे वह अचानक कहीं चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने मेले में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद घर लौटकर आस-पास, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां भी तलाश की गई, फिर भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। परिजनों को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ भगा लिया है। लगातार तलाश के बाद 28 जनवरी को थाना ब्योहारी में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफमामला दर्ज कराया गया।

यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही भोपाल ने एस.आई.आर.टी. भोपाल को एक तरफा मुकाबले में 07 विकटों से हराया

विदिशा। सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान में आयोजित 23वीं श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के छठवें दिन सोमवार को यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही भोपाल विरूद्ध एस.आई.आर.टी. भोपाल के मध्य खेला गया। यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही भोपाल ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। एस.आई.आर.टी. भोपाल ने पहले खेलते हुये निर्धारित 20 ओर्वस में आठ विकेट खोकर 147 रन बनाये, एस.आई.आर.टी.भोपाल के बल्लेबाज करण शर्मा ने 2 चैके 01 छक्के की मदद से 38 गेंदों पर 35 रन बनाये वहीं उनका साथ देते हुए अज़ान खॉन ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाये इस पारी में उन्होने 01 चौके और 02 छक्के मारे। यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही भोपाल के गेंदबाज तरंग ने 04 ओवर्स में 11 रन देकर 02 विकेट व भारतल असनानी ने 04 ओवर्स में 22 रन देकर 02 विकेट हासिल किये। जबाब में खेलते हुए यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही भोपाल ने एक तरफा मुकाबले में एस.आई.आर.टी. भोपाल को मात्र 12 ओवर में 150 रन बना कर हरा दिया। हिमांश मेवाड़ा ने मात्र 24 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाये इस पारी में उन्होंने 12 चैके और 03 छक्के लगाये।

रीवा में खेत की बाउंड्री को लेकर विवाद, सरिया से किया हमला

रीवा। रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र के पड़रा गांव में खेत की बाउंड्री कराने को लेकर पारिवारिक विवाद खूनी झड़प में बदल गया। सोमवार को विवाद के दौरान एक युवक के सिर पर सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी गोपाल कृष्ण द्विवेदी (23) पुत्र श्यामधर द्विवेदी निवासी ग्राम पड़रा ने अपने बड़े पिता रिपुसूदन प्रसाद द्विवेदी के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल अपने वैरिहाई स्थित खेत में गड्ढा खुदवाकर बाउंड्री का काम करा रहा था। इसी दौरान परिवार के ही कृष्णधर द्विवेदी और उनका बेटा रोहित द्विवेदी मौके पर पहुंचे और बाउंड्री निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद करने लगे। दोनों पर पहले गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर मारपीट शुरू करने का आरोप लगाया है। गोपाल ने बताया कि कृष्णधर ने उसे पकड़ लिया और रोहित ने लोहे की सरिया से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। इससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। शोर सुनकर रामानुज पाण्डेय और रिपुसूदन प्रसाद मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। पीड़ित का कहना है कि घटना के दौरान रजनीश द्विवेदी भी वहां पहुंच गया और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में गोपाल के सिर के अलावा बाएं हाथ, दाहिने पैर और पीठ में भी चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन घायल गोपाल को रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है।

कैलाश मानसरोवर जाने का सपना होगा पूरा

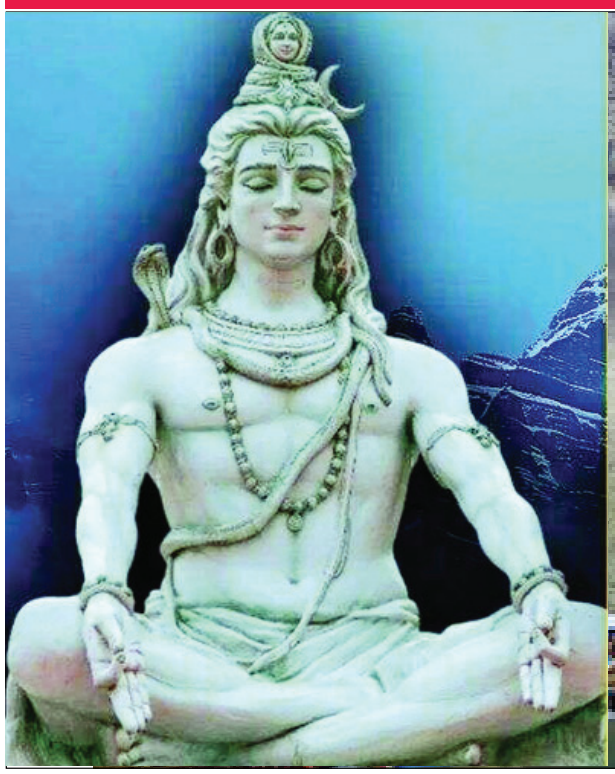

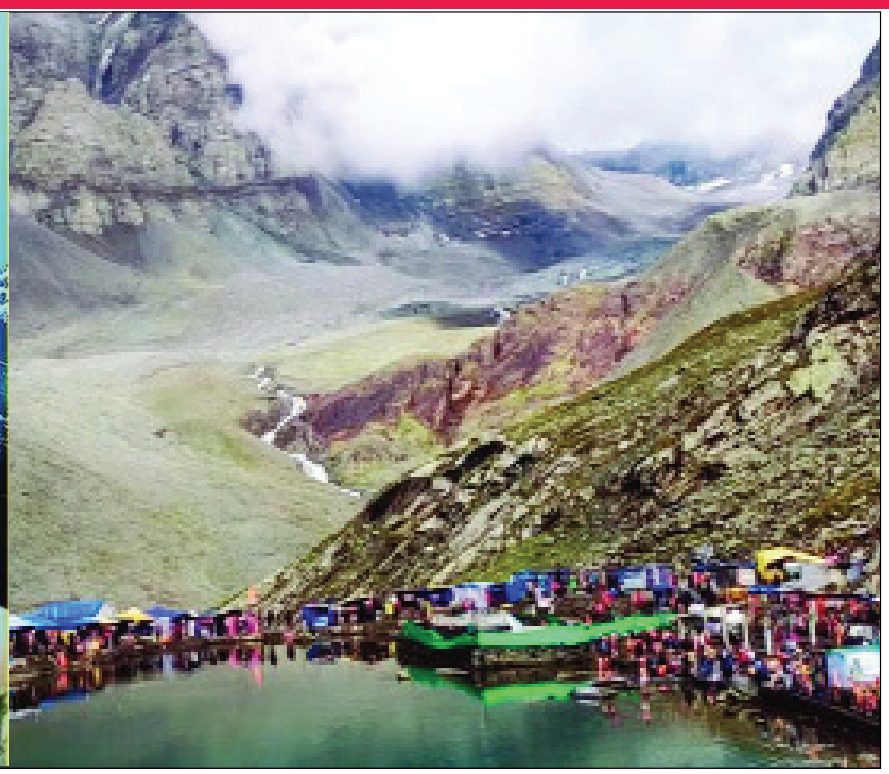

अगर आप 2026 में बिना पासपोर्ट और वीजा के आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा एक शानदार विकल्प है। साल 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के बीच जबरदस्त उत्साह है। हर साल हजारों भक्त भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश पर्वत और पवित्र झील मानसरोवर के दर्शन के लिए निकलते हैं। आमतौर पर यह यात्रा चीन (तिब्बत) क्षेत्र में होने के कारण पासपोर्ट और वीजा के माध्यम से की जाती है, लेकिन भारत में एक ऐसा मार्ग भी है जहां पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप 2026 में बिना पासपोर्ट और वीजा के आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा एक शानदार विकल्प है। हालांकि यदि आप वास्तविक कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन करना चाहते हैं, तो पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य हैं। आइए जानते हैं 2026 में इस यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी।

बिना पासपोर्ट और वीजा कैसे संभव है यात्रा?

भारत सरकार द्वारा संचालित आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा उत्तराखंड मार्ग के की जाती है। श्रद्धालु बिना पासपोर्ट-वीजा के इस मार्ग पर यात्रा के लिए जा सकते हैं। यह यात्रा पूरी तरह भारत की सीमा के अंदर होती है। यह मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरता है। इस यात्रा में श्रद्धालु आदि कैलाश (छोटा कैलाश) और ओम पर्वत के दर्शन करते हैं। ध्यान रखें यह यात्रा तिब्बत स्थित मुख्य कैलाश पर्वत नहीं बल्कि भारत में स्थित पवित्र स्थलों की यात्रा है।

आदि कैलाश क्या है?

आदि कैलाश को 'छोटा कैलाश' भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थल भगवान शिव का ही एक पवित्र स्वरूप माना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को विशेष अनुभव प्रदान करता है।

ओम पर्वत का महत्व

ओम पर्वत की खासियत यह है कि इसकी चोटी पर प्राकृतिक रूप से बर्फ से '?' का आकार बनता है। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत आस्था और आकर्षण का केंद्र है।

2026 में यात्रा कब शुरू होगी?

आमतौर पर यह यात्रा मई से सितंबर के बीच आयोजित की जाती है, जब मौसम अनुकूल रहता है। 2026 के लिए आधिकारिक तिथियों की घोषणा उत्तराखंड सरकार या संबंधित पर्यटन विभाग द्वारा की जाएगी। यात्रा के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना आवश्यक आयु सीमा आमतौर पर 18 से 70 वर्ष

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि

कैलाश मानसरोवर की यात्रा का संभावित रूट

बिना वीजा पासपोर्ट के कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए उत्तराखंड मार्ग का चयन करें। इसमें दिल्ली से हल्द्वानी होते हुए पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक की यात्रा की जाती है। यह पूरा मार्ग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है।

यात्रा का अनुमानित खर्च

प्रति व्यक्ति पैकेज 35,000 रुपये से 60,000 रुपये तक सुविधाओं के अनुसार खर्च आ सकता है। इसमें आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन और परमिट शामिल हो सकते हैं। 'अतिथि देवो भवः' की तर्ज पर होगा स्वागत, ऋषिकेश-विकासनगर में 24 घंटे होंगे रजिस्ट्रेशन देहरादून धर्मयात्रा पर निकला रामादल, बिखरे आस्था के रंग सीतापुर नौ दिवसीय संगीतमयी श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ, भव्य कलश यात्रा निकली

सिद्धार्थनगर

केदारनाथ जा रहे हैं तो ये काम अवश्य कर लें, वरना बिना दर्शन के लौटना पड़ेगा रामादल धर्म यात्रा को तैयार, होगी पुष्प वर्षा सीतापुर

मुख्य कैलाश मानसरोवर यात्रा

अगर कोई श्रद्धालु तिब्बत स्थित वास्तविक कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करना चाहता है, तो उसे पासपोर्ट, चीनी वीजा, मेडिकल टेस्ट और विदेश मंत्रालय द्वारा चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह यात्रा आमतौर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है।

यात्रा से जुड़ी जरूरी सावधानियां

हाई एल्टीट्यूड के कारण स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयां साथ रखें मौसम अपडेट लेते रहें अधिकृत एजेंसी से ही बुकिंग करें।

मां-बेटे के बीच बढ़ती दूरियों की क्या वजह है?

आइए जानते हैं मां-बेटे के बीच लड़ाई क्यों होती है और लड़ाई के बाद भी रिश्ते को सुधारने के लिए क्या किया जाए। आज के डिजिटल दौर में रिश्तों की परिभाषा तेजी से बदल रही है। पहले जहां मां-बेटे का रिश्ता त्याग, समझ और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक माना जाता था, वहीं अब पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर कई बार टकराव का कारण बन जाता है। जहां पहले बेटे और पिता के बीच एक छुपी हुई दीवार हुआ करती थी, वहीं अब मां और बेटे के बीच का संवाद भी बहस में बदलने लगा है। सवाल यह नहीं कि मां-बेटे में लड़ाई क्यों होती है, सवाल यह है कि इन लड़ाइयों के बाद रिश्ते को कैसे बचाया जाए। हर मां चाहती है कि उसका बेटा सुरक्षित और सफल

रहे। हर बेटा चाहता है कि उसकी मां उस पर भरोसा करे। जब भरोसा और संवाद जुड़ जाते हैं, तो लड़ाइयां रिश्ते को तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। आइए जानते हैं मां-बेटे के बीच लड़ाई क्यों होती है और लड़ाई के बाद भी रिश्ते को सुधारने के लिए क्या किया जाए।

क्यों बढ़ रही हैं मां-बेटे के बीच लड़ाइयां?

पीढ़ियों का गैप: मां पारंपरिक सोच में पली-बढ़ी होती है, जबकि बेटा डिजिटल और आधुनिक माहौल में। मां पढ़ाई, अच्छे नंबर की चाह रखती हैं, बेटा स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज को प्राथमिकता देता है। मां को स्थिर नौकरी पसंद है, बेटा स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग चुनना चाहता है।

यहीं से शुरू होता है मतभेद।

कंट्रोल बनाम आज़ादी: मां को लगता है कि वह बेटे की भलाई के लिए रोक-टोक कर रही है। बेटे को लगता है कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। जब मां और बेटे के बीच नियंत्रण और आजादी का भाव टकराता है तो विवाद बढ़ता है।

डिजिटल दूरी

आज की दुनिया में मोबाइल और सोशल मीडिया ने संवाद कम और गलतफहमियां ज्यादा बढ़ाई हैं। घर में साथ रहते हुए भी भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है।

आर्थिक और करियर दबाव

बेरोजगारी, करियर स्ट्रेस और शादी का दबाव अक्सर गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है, जिसका असर मां-बेटे के रिश्ते पर पड़ता है।

लड़ाई के बाद रिश्ते कैसे सुधारें?

खुलकर बातचीत करें: चुप्पी रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। 'तुम हमेशा ऐसा करते हो' जैसे आरोप लगाने से बचें। बल्कि बातचीत से रिश्ता सुधारें।

इमोशनल रोल समझें: मां सिर्फ नियम बनाने वाली नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का आधार होती है। बेटा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सपनों से भरा इंसान भी है। दोनों को अपनी और एक दूसरे की भावनात्मक भूमिका स्पष्ट पता होनी चाहिए।

सुपर-8 के पहले मैच में हार से बिगड़ा भारत का गणित, नेट रन रेट बना नई टेंशन!

खेल एजेंसी

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में पहले ही मैच भारत की हार निराशाजनक रही। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 76 रन से करारी शिकस्त दी। इस हार ने न सिर्फ अंक तालिका में भारत को पीछे धकेला, बल्कि नेट रन रेट पर भी गहरी चोट पहुंचाई। सुपर-8 के दो ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप में चार-चार टीमें हैं। हर ग्रुप से शीर्ष-दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर-8 ग्रुप 1 में दक्षिण अफ्रीका दो अंकों और +3.800 के शानदार नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत एक मैच में हार के बाद शून्य अंक और -3.800 ह्रक्रक के साथ सबसे नीचे खिसक गया है। -3.800 नेट रन रेट का मतलब है कि भारत को अगले दोनों मैच भारी अंतर से जीतने होंगे। हालांकि, दोनों मैच में जीत भी भारत को सेमीफाइनल की गारंटी नहीं देता है। सुपर-8 ग्रुप-1 की बाकी दो टीमें, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे आज एक-दूसरे के खिलाफ अपने सुपर-8 अभियान की शुरुआत करेंगी। स्पष्ट है कि भारत के लिए अपना और ग्रुप की दूसरी टीमों का भी, यानी आगे का हर मैच निर्णायक बन चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187/7 का मजबूत स्कोर बनाया। डेविड मिलर (63) और डेवाल्ड ब्रेविस (45) ने मध्य ओवरों में तेज रन बटोरकर भारत को बैकफुट पर ला दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3/15 की बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन अन्य गेंदबाज लय में नहीं दिखे। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्यकुमार की कप्तानी वाली टीम कभी भी मुकाबले में नियंत्रण बनाती नजर नहीं आई। पूरी टीम 111 रन पर सिमट गई। मार्को यानसेन ने चार विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। भारत को अब वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने दोनों शेष मुकाबले जीतने होंगे। जिम्बाब्वे से भारत का सामना 26 फरवरी को चेन्नई में और वेस्टइंडीज से भारत का सामना एक मार्च को कोलकाता में है। यदि भारत दोनों मैच जीतता है, तो उसके चार अंक हो जाएंगे। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतता है तो उसके छह अंक होंगे और टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे में भारत के लिए चार अंक सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगे। क्योंकि बाकी दोनों टीमें अधिकतम दो-दो अंक तक ही रह पाएंगी। सेमीफाइनल में पहुंचने का यह सबसे आसान समीकरण है। हालांकि, सबसे बड़ा पेच तब फंसेगा, जब दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने बाकी दो में से सिर्फ एक मैच जीतती है और वेस्टइंडीज या जिम्बाब्वे में से कोई टीम दक्षिण अफ्रीका को हरा देती है। ऐसे में तीन टीमें 4-4 अंकों पर पहुंच सकती हैं। तब फैसला नेट रन रेट से होगा। भारत का मौजूदा नेट रन रेट (-3.800) काफी कमजोर है, इस स्थिति में भारत को बाकी दोनों मैचों में बड़ी जीत की जरूरत होगी। दक्षिण अफ्रीका चोकर्स माने जाते हैं और जिम्बाब्वे या वेस्टइंडीज की टीम फंसा सकती है। अगर दक्षिण अफ्रीका अपने बाकी दोनों मैच हार जाता है, तो इस स्थिति में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों के दो-दो अंक तय हो जाएंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका दो ही अंकों पर सिमट कर रह जाएगा। इस स्थिति में अगर भारत जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों को हरा देता है तो टीम इंडिया के चार अंक पक्के हो जाएंगे।

ब्रूक की कप्तानी पारी ने इंग्लैंड को दिलाया सेमीफाइनल का टिकट

पल्लेकल। इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को दो विकेट से हराया। इंग्लैंड के लिए कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक लगाया, जिससे टीम लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक कर सकी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19.1 ओवर में आठ विकेट पर 166 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इंग्लैंड के लिए ब्रूक ने सर्वाधिक 100 रन बनाए जिससे टीम ने सुपर आठ में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने इस तरह सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि पाकिस्तान के लिए आगे की राह बेहद कठिन हो गई है। पाकिस्तान का पिछला मुकाबला बारिश में धुल गया था और अब उसका एक मैच शेष है। अगर पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जीत भी लेती है तो उसके तीन ही अंक होंगे। वहीं, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के पास पाकिस्तान को पीछे छोड़ने का मौका होगा। इंग्लैंड के लिए ब्रूक के अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। इंग्लैंड की सर्वाधिक बार लगातार टी20 विश्व कप के पहुंचने सेमीफाइनल वाली टीम बन गई है। इंग्लैंड ने लगातार पांचवीं बार ऐसा किया है। उसने इस मामले में पाकिस्तान और श्रीलंका को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान और श्रीलंका ने लगातार चार बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड की टीम 2016, 2021, 2022, 2024 और 2026 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शाहीन अफरीदी ने टीम को लगातार झटके दिए। शाहीन ने पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा और फिर जोस बटलर को आउट किया जो दो रन बनाकर आउट हुए। शाहीन ने फिर पावरप्ले के दौरान जैकब बेथेल को आउट कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। बेथेल आठ रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि, ब्रूक टिके रहे और उन्होंने जिम्मेदारी से खेलते हुए पारी आगे बढ़ाई। ब्रूक ने पहले 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और फिर 50 गेंदों पर शतक लगाया। ब्रूक टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान हैं। इतना ही नहीं, ब्रूक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

हार्दिक ने एक्स-वाइफ और बेटे को गिफ्ट की लग्जरी कार

खेल एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने अपनी एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक और बेटे अगस्त्य पंड्या को शनिवार को एक लग्जरी कार गिफ्ट की है। कार डिलीवरी के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। हार्दिक ने बेटे को लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल, लैंड रोवर मुंबई के इंस्टाग्राम पेज पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, हार्दिक पंड्या ने एक बार फिर अपनी डिफेंडर खरीदने के लिए नवनीत मोटर्स को चुना। भरोसे पर बना रिश्ता। उत्कृष्टता पर टिका फैसला। मुंबई में डिलीवर, लैंड रोवर डिफेंडर। अगस्त्य पंड्या और स्टेनकोविक को प्रेजेंट। दमदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार। आगे बढ़कर नेतृत्व करने वालों के लिए बनाई गई। बता दें कि हार्दिक ने मई 2020 में नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी। उसी साल नताशा ने बेटे अगस्त्य को 30 जुलाई 2020 को जन्म दिया।

पावरप्ले में 'पावर' गायब! : टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी क्यों हो रही फेल?

खेल एजेंसी

अहमदाबाद। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ओपनिंग जोड़ी लगातार फ्लॉप रही है। पांच मैचों में सलामी बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 34 रन जोड़ सके। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की अच्छी शुरुआत देने में नाकामी से टीम दबाव में है। प्लेइंग-11 में बदलाव और दाएं-बाएं बल्लेबाजों के असंतुलन ने भी टीम की रणनीति को कमजोर किया है। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग जोड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। रविवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में भी भारत की सलामी जोड़ी ने फैंस को निराश किया। भारत को टी20 वर्ल्ड कप के पांच मुकाबलों में सलामी जोड़ी ने महज 34 रन दिलाए हैं। इनमें चार मैचों में ईशान-अभिषेक की जोड़ी और एक मैच में ईशान-सैमसन की जोड़ी शामिल है। नामीबिया के खिलाफ अभिषेक नहीं खेले थे और सैमसन ने ओपनिंग की थी। दक्षिण अफ्रीका से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। हालांकि, ईशान की पारी का अंत सिर्फ चार गेंदों में हो गया और भारतीय टीम की सलामी जोड़ी स्कोरबोर्ड पर एक रन भी नहीं लगा सकी। विकेटकीपर-बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटा। वहीं, अभिषेक 15 रन बनाकर आउट हुए। यह हाल सिर्फ इस मैच का नहीं है, बल्कि अब तक खेले गए पांच मुकाबलों में भारत की सलामी जोड़ी का यही हश्र रहा है।

अमेरिका के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में अभिषेक और ईशान किशन पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे थे। हालांकि, यह साझेदारी सिर्फ आठ रनों तक ही चल सकी और अभिषेक बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। नामीबिया के खिलाफ अभिषेक के बीमार होने की वजह से ईशान किशन को संजू सैमसन के रूप में नया जोड़ीदार मिला था। हालांकि, नतीजा कुछ खास नहीं रहा।

210 ग्राम पंचायतों में पहुँचा कृषि रथ

कृषि रथ के माध्यम से जिले के 6720 किसानों को दी गई सलाह

हरदा। म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। म.प्र. शासन एवं कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन में हरदा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कृषि रथ का संचालन 11 जनवरी से 11 फरवरी तक किया गया। उप संचालक कृषि श्री जे.एल. कास्दे ने बताया कि जिले के विकासखंडो में संचालित कृषि रथों द्वारा 210 ग्रामपंचायतों में भ्रमण किया गया। इस दौरान 6720 कृषक तथा 630 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों व वैज्ञानिको ने किसानों को विस्तृत जानकारी दी। कृषि रथ के साथ कृषि विज्ञान केंद्र, कोलीपुरा के वैज्ञानिक, कृषि विभाग एवं संबद्ध विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा किसानों से सीधा संपर्क कर ई-विकास प्रणाली से उर्वरक क्रय करने, ग्रीष्मकालीन मूंग के स्थान पर उडद, मूंगफली एवं

तिल फसल लगाने, फसल कटाई उपरांत शेष अवशेष यथा नरवाई प्रबंधन हेतु, उन्नत कृषि यंत्रो जैसे सुपरसीडर, मल्चर, रोटावेटर इत्यादि का उपयोग कर नरवाई को मृदा में अपघटित करने एवं प्राकृतिक व जैविक कृषि करने, मृदा स्वास्थ कार्ड के आधार पर उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करने और भूमि पर बोई गई फसल अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वो के उपयोग करने हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित किया गया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं तथा समसामयिक सलाह प्रदान की गई। उप संचालक श्री कास्दे ने बताया कि कृषि रथ कार्यक्रम के सफल संचलन में कृषि विस्तार अधिकारियो, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक व सहायक तकनीकी प्रबंधक, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के मैदानी अमले की सक्रीय भागीदारी रही है।

विकसित भारत रोजगार मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी के लिए हरदा में शुरू होगा जन-संवाद अभियान

हरदा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हरदा जिले में व्यापक आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के निर्देशों के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन ने जिले की सभी जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए विस्तृत कार्ययोजना जारी की है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जोसेफ ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को न केवल रोजगार का वैधानिक अधिकार देना है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना है जहाँ काम के बदले पारदर्शी और त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो, योजना का निर्माण और क्रियान्वयन पूरी तरह पंचायत स्तर पर हो तथा सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता रहे। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जोसेफ ने अभियान को गति देने के लिए सप्ताह-वार थीम आधारित गतिविधियों का निर्धारण किया है। जारी कार्यक्रम अनुसार पहला सप्ताह 23 से 28 फरवरी अंतर्गत भ्रम बनाम तथ्य तथा रोजगार से परिसम्पत्ति तक पर मीडिया संवाद कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जावेगा, जिसमें मुख्य तथ्य 125 दिन रोजगार की गारंटी, देरी से भुगतान से संबंधित प्रावधान, पंचायत की भूमिका तथा ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सृजन आधारित गतिविधियां शामिल हैं। दूसरा सप्ताह 2 से 7 मार्च तक के तहत अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस अंतर्गत ग्राम स्तर पर सामूहिक शपथ, बैनर/पोस्टर का प्रदर्शन संबंधी आधारित गतिविधियां शामिल है। तीसरा सप्ताह 9 से 14 मार्च तक के तहत विकसित भारत ग्राम संवाद अंतर्गत संवाद-चौपाल/ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय बैठक, दीवार लेखन/फ्लैक्स संबंधी आधारित गतिविधियां शामिल है। चौथा सप्ताह 16 से 21 मार्च तक अहिंसा से अधिकार थीम आधारित गतिविधियां अंतर्गत चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, जागरूकता यात्रा संबंधी गतिविधियां शामिल है। पाँचवा सप्ताह 23 से 28 मार्च के अंतर्गत जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा, नए अधिनियम पर प्रस्तुतीकरण तथा पुराने कानून की कमियों का समाधान आधारित गतिविधियां शामिल है।

खिरकिया कॉलेज में 200 छात्रों का हेल्थ चेकअप

स्टूडेंट्स को खून की कमी, शुगर, कमजोरी, डॉ. बोले- सही खान-पान से ठीक करें

खिरकिया। खिरकिया के सरकारी कॉलेज में सोमवार को ब्लड टेस्ट कैंप लगाया गया। इस दौरान करीब 200 छात्र-छात्राओं की सेहत की जांच की गई। इस कैंप का असली मकसद बच्चों को अपनी सेहत का ख्याल रखने और बीमारियों के प्रति जागरूक करना था। कॉलेज के प्रिंसिपल आर. एस. पटेल और प्रभारी पवन कुमार दोहरे की देखरेख में यह कैंप लगा। खिरकिया अस्पताल की टीम ने कॉलेज पहुंचकर बच्चों के ब्लड सैंपल लिए। कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी छात्रों को समझाया कि समय-समय पर अपनी जांच कराना क्यों जरूरी है। इस कैंप में सीबीसी, ब्लड शुगर, लिवर, किडनी और थायरॉइड जैसे जरूरी टेस्ट किए गए। इन टेस्ट से शरीर में खून की कमी, शुगर, कमजोरी, इन्फेक्शन या हार्मोन की दिक्कतों का शुरू में ही पता चल जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर बीमारी का शुरुआत में पता चल जाए, तो सही खान-पान और इलाज से उसे जल्द ठीक किया जा सकता है। छात्रों ने इस पहल की काफी तारीफ की और इसे अपने लिए बहुत फायदेमंद बताया। कॉलेज मैनेजमेंट

ने कहा है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए आगे भी इस तरह के कैंप लगाए जाते रहेंगे।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत हंडिया में स्क्रीनिंग शिविर आज

हरदा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित सभी पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों की पेंशन फार्म तैयार कर पेंशन स्वीकृत करने एवं उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु जिले में स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री कमलेश सिंह ने बताया कि शिविरों में सामाजिक न्याय विभाग, स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग, एवं महिला बाल विकास, सभी जनपदों व नगरीय निकायों को शत प्रतिशत स्क्रीनिंग हेतु जिम्मेदारी दी गई है। उप संचालक श्री सिंह ने बताया कि शासन द्वारा जिले में निर्धारित दिनांक एवं स्थान तय किए गए है, जिसकी जिम्मेदारी सर्व संबंधित विभागों को सौपी गई है। उन्होने बताया कि 25 फरवरी को ग्राम पंचायत हंडिया में प्रात: 11 बजे से शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार 27 फरवरी को ग्राम पंचायत रहटगांव, 09 मार्च को ग्राम पंचायत गोराखाल, 11 मार्च को ग्राम पंचायत चारूवा तथा 13 मार्च को ग्राम पंचायत सोडलपुर में स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किये जायेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक लोमेश कुमार गौर द्वारा दिशागोचार प्रकाशन, 26-बी प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल से मुद्रित तथा सी-5 खेतवाली माता मंदिर के पास महाराणा प्रताप कालोनी हरदा जिला हरदा म.प्र. से प्रकाशित
संपादकः- लोमेश कुमार गौर मो. 9826696230 Email-bhuanakimati@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरदा कोर्ट रहेगा)।